

खेलों का बदलता चेहरा और खिलाड़ियों का बढ़ता आत्मविश्वास

हम 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से खेल बिरादरी से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में प्रत्येक भारतीय ने हमारे एथलीटों के प्रदर्शन का तहे दिल से स्वागत किया है। हालांकि ओलंपिक में पदकों की संख्या सिर्फ सात है, लेकिन यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और हमारे पैरा एथलीटों का प्रदर्शन असाधारण है। हमने कई कारणों से अतीत में खराब प्रदर्शन किया था। हालांकि, हम चीन, अमेरिका, जापान और अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं और लेकिन, हाल के दिनों में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रति दृष्टिकोण और कार्यों में बदलाव आया है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, फिर भी, केंद्र सरकार और खेल प्राधिकरणों ने आने वाले वर्षों में इसे गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यपद्धती विकसित और निर्धारित की है।

पिछले सात वर्षों में खेल मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास :

पीएम मोदी के कुछ उद्धरण जो देश में खेलों के प्रति सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं:

“एक देश की छवि केवल आर्थिक और सैन्य ताकत के बारे में नहीं है। किसी देश के कोमल चेहरे से भी फर्क पड़ता है। खेल एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच सकती है।

“यदि खेल हमारे जीवन में महत्व नहीं रखते हैं, तो हम अपने समाज में एक “संस्कार” के रूप में खेल भावना का पोषण नहीं कर सकते हैं और ऐसे “संस्कारों” के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है!

“खेल हमारे सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य और अविभाज्य हिस्सा बनना चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्फ एक उपोत्पाद है।”

खेलो इंडिया :

खेलो इंडिया योजना 2016 में तीन पूर्व योजनाओं के एकीकरण के बाद शुरू की गई थी। यह योजना वार्षिक खेलकूद और प्रतियोगिताओं में युवाओं की बढ़ती हुई भागीदारी पर तल्लीन थी। खेलो इंडिया (खेल योजना के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का लक्ष्य खेल में सामूहिक भागीदारी और विशालता की प्रगति के दोहरे लक्ष्यों को पूरा करना है। योजना “सभी के लिए खेल” के साथ-साथ “उत्कृष्टता के लिए खेल” को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।

खेलो इंडिया विशेष रूप से एक नया संस्करण वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक गेम चेंजर है। महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के उद्देश्य से बारह कार्यक्षेत्रों के साथ, इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को संबोधित करना और उन्हें भारत की खेल संस्कृति का हिस्सा बनाना है।

व्यक्तिगत और स्थानीय क्षेत्र के विकास, मौद्रिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक साधन के रूप में खेल को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में इस योजना में बदलाव किया गया था।

लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना

खेल मंत्रालय ने २०१६, २०२० और अब २०२४ के ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं में मदद करने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के तहत मई २०१५ में 'टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप)' योजना जारी की। एथलेटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है।, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी के खेल अहम हैं। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा करते हैं, जो 10 सदस्यीय पैनल है जिसमें प्रकाश पादुकोण (बैडमिंटन), पीटी उषा (एथलेटिक्स) शामिल हैं।

इसका उद्देश्य 2020 और 2024 ओलंपिक में संभावित पदक विजेताओं की पहचान करना है।

इन एथलीटों को 8 साल तक प्रति वर्ष पांच लाख रुपये, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा, यह कार्यक्रम 8 वर्षों के लिए सालाना 1000 नए एथलीटों को जोड़ेगा। इस प्रकार, इस कार्यक्रम की परिकल्पना है कि 15 वर्षों के अंत में, हमारे पास हर फोकस खेल में बड़ी संख्या में चैंपियन एथलीट तैयार होंगे।

इसके अलावा, युवा एथलीटों को छात्रवृत्ति प्रदान करके, सरकार उनके लिए वित्तीय स्थिरता के प्रश्न का समाधान करना चाहती है। वे खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प बनाना चाहते हैं। अधिकांश एथलीटों, स्कूलों और माता-पिता के लिए वित्तीय स्थिरता मुख्य चिंताओं में से एक थी, इसलिए कई छात्रों के पास आवश्यक प्रतिभा, कौशल और जुनून होने के बावजूद भागीदारी बहुत कम थी। हमने अतीत में देखा था कि कैसे एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल के बाद जीवन का सामना करता था इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत करने की इस सरकार की पहल एक स्वागत योग्य और बहुत जरूरी कदम है। इस संबंध में, सरकार ने TOPS एथलीटों के लिए समर्थन बढ़ाया है, जो कोई भी भारत में खेल को करियर के रूप में चुनना चाहता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह किसी भी तरह से एथलीटों के प्रदर्शन को कमजोर या प्रभावित न करे। यही कारण है कि सरकार ने टॉप्स के तहत कवर किए गए हमारे स्टार एथलीटों को 50,000 रुपये प्रति माह के जेब खर्च के रूप में योग्य बनाने का फैसला किया है। खेल को आर्थिक रूप से एक करियर के रूप में व्यवहार्य बनाने की दिशा में यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। वैसे, यह राशि हमारे एथलीटों को पहले से मिलने वाले आहार और अन्य भत्तों के अतिरिक्त है।

खेल प्रतिभा खोज पोर्टल

अगस्त 2017 में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भारत के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की पहचान करने के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल युवाओं को अपनी उपलब्धियों को अपलोड करने की अनुमति देता है। जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन्हें फिर ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और योग्य उम्मीदवार भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की योजनाओं में भाग लेते हैं।

2017 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला खिलाड़ियों की शिकायतों और शिकायतों को दूर करने और हल करने के लिए एएस और एफए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इससे महिला एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन करने का हौसला मिला है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना

सरकार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के रूप में उनकी जीत और प्रतिज्ञाओं के लिए अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के साथ खेल हस्तियों को लगातार सम्मानित और सम्मानित करती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल और खेल योजना

इस योजना के तहत निःशक्तजन खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने और दिव्यांग खिलाड़ियों वाले स्कूलों और संस्थानों की सहायता करने के लिए उनके क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इस फोकस ने टोक्यो में हमारे पैरा एथलीटों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया।

पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए अपना उचित योगदान दिया है। पीएम मोदी खुद फिटनेस के अवतार हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं और साथी नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का सुझाव देते हैं। खेलों में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से और क्या किया जा सकता था, इस पर कोई बहस नहीं है।

अंडर-14 एवं अंडर-17 वर्ग में राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन हेतु खेलों के विकास हेतु राष्ट्रीय योजना।

इसमें स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट्स (IGMA) के तहत कबड्डी, खो-खो, कलारियापट्टू जैसे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना शामिल है।

यह योजना सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी फील्ड, स्विमिंग पूल, हॉल प्रदान से विकास करती है।

मिशन इलेवन मिलियन (एमएक्सआईएम)।

ऊरजा : सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स द्वारा शुरू की गई अंडर -19 फुटबॉल प्रतिभा खोज।

अन्य :

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (NSTC)

आर्मी बाँयज स्पोर्ट्स कंपनी (एबीएससी)

साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

एसटीसी/एसएजी का विस्तार केंद्र

उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

राष्ट्रीय खेल अकादमियां (एनएसए)

विभिन्न खेलों में 8-25 आयु वर्ग के प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण) की पहल ऊपर दी गई है।

दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम :

चैंपियन बनाने की तरकीब है युवा प्रतिभाओं को पकड़ना। ठीक यही सरकार के दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है।

इस कार्यक्रम के तहत, विशेषज्ञ हर साल 1000 नवोदित युवा एथलीटों को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और विभिन्न अन्य राष्ट्र चैंपियनशिप के माध्यम से चुनते हैं।

क्रिकेट और अन्य खेलों के बीच भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है; इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी कम हुआ है। अब हमारे देश के पीएम हर खेल और एथलीट के लिए जयकार कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, मदद कर रहा है, किसी एथलीट या टीम की उपलब्धि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित कर रहा है, तो पूरा भारत उन एथलीटों के लिए जयकार करने लगा, जिसके वजह से बड़ा बदलाव आया।

भारोत्तोलक मीराबाई चानू का मामला तो सभी जानते हैं कि कैसे पीएम और टीम ने यूएसए में इलाज कराने में उनकी मदद की। एथलीटों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, हालांकि यह चीन की तुलना में कम है, लेकिन हम भविष्य में विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में चल रहे वृद्धिशील प्रयासों के साथ बड़ा बदलाव देखेंगे।

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय :

खेल और एथलीट विकास योजना की दिशा में एक बड़ा कदम, इम्फाल, मणिपुर में चार स्कूलों और तेरह विभागों के साथ बनाया गया एकमात्र खेल विश्वविद्यालय :

खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा स्कूल

खेल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी स्कूल

खेल शिक्षा स्कूल

अंतःविषय अध्ययन स्कूल

संपूर्ण 360° स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का लगभग हर पहलू इसमें जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय ने पहले से ही पाठ्यक्रमों की पेशकश शुरू कर दी है, और हम उन पाठ्यक्रमों की पेशकश देश भर में चल रहे पायलट केंद्रों के माध्यम से करेंगे।

मोदी सरकार के तहत भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे खेल संगठन विभिन्न प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय खेलों के स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

भारतीय अब निर्विवाद रूप से खेलों की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। क्रिकेट अब भारतीयों की शान का इकलौता खेल नहीं रह गया है। वे अब अन्य खेलों में भी तल्लीन हो सकते हैं।

(लेखक समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं व कई पुस्तकें लिख चुके हैं)

संपर्क

7875212161